(3) श्रमिकों के अधिक संख्या वाले कुछ क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के डीपुओं में अपर्याप्त स्टाक का होना ।

(4) सड़क मार्ग द्वारा खाद्यान्नों को लाने-ले जाने में कठिनाई तथा रेलवे वैगनों के आवंटन में विलम्ब ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तिलक नगर में निर्माणों का गिराया जाना

3275. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1975 में तिलक नगर क्षेत्र में गिराई गई दुकानों/स्टालों के वास्तविक मालिकों को दुकानों। स्टालों का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक योजना तैयार की थी जिसके अधीन उन दुकानदारों को किस्तों के आधार पर दुकानें स्टाल आवंटित करने की व्यवस्था थी जो पैसे की कमी के कारण जनकपुरी में सब्जी मंडी में दुकान नहीं खरीद सके थे ;

(ग) इस योजना के अधीन दुकानों/स्टालों के आवंटन के लिए अलग अलग कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोगों को उनकी पसन्द के अनुसार दुकान अथवा स्टाल आवंटित कर दिए ;

(घ) शेष लोगों को स्टाल कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार तिलक नगर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों स्टालो का आवंटन करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यह एक सामान्य योजना थी और यह केवल उन्ही तक सीमित नही थी जो छोटी सब्जी मंडी में दुकान नही खरीद पाए थे । इस योजना के अन्तर्गत दुकानो/स्टालों के आवटन के लिए सफाई अभियान के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से हटाए गए विस्थापितों से 591 आवेदन पत्र (520 दुकानों और 71 स्टालों के आवटन के लिए) प्राप्त हुए थे । इनमें से आवंटन के लिए पात्र पाए गए 101 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्लाट की लाटरी के द्वारा दुकान स्टाल आवंटित किए गए । ये जनकपुरी में दुकान के प्लाट आवंटित किए गए 377 व्यक्तियों के अतिरिक्त थे ।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी, हां ।

ट्रैक्टरों का आयात

3276. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात किया जाएगा क्योंकि देश में उनका उत्पादन बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से ट्रैक्टरो का आयात किया जाएगा, और

(ग) विभिन्न राज्यों को ट्रैक्टरों का वितरण किन आधारों पर किया जाएगा और वितरण का अनुपात क्या होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नही । ट्रैक्टरों की मांग की पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त है ?

(ख) और (ग). प्रश्न ही नही होता ।

Edible oil and support price of oilseeds

3277. SHRI OSCAR FERNANDES. Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total production and consumption of edible oils in the country. State-wise, and what are the reasons for the shortage of edible oils in the country; and

(b) the steps which Government propose to take in order to give support price to oilseeds for giving encouragement to their production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Extraction of edible oils from oilseeds is in the organised and unorganised industrial sectors. The total production of edible oils in the country State-wise is, therefore, not available. However from the figures of total production of edible oilseeds it is estimated that production of edible oils during 1979-80 is about 27 lakh tonnes and the consumption requirement is estimated at about 37 lakh tonnes. The reason for the shortage of edible oils

in the country is the shortfall of oilseeds production in 1979-80 due to drought and the resultant widening gap between demand and supply.

(b) For encouraging the production of oilseeds the Government have been announcing support prices for groundnut, rapeseed and mustard, soyabean and sunflower seeds. The support prices have been generally revised upwards every year fo giving encouragement to oilseeds production. For the same purpose, State Governments and the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India are required to undertake purchase operations at support price levels.

U.G.C. grants to colleges in backward and rural areas

3278. SHRI OSCAR FERNANDES: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the procedure adopted by the University Grants Commission for giving grants to colleges situated in the backward areas and rural areas;

(b) whether Government propose to give more concessions and grants to colleges located in the remote areas; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKRANAND): (a) The Commission had relaxed the conditions of eligibility for development grants in favour of colleges located in backward and rural areas, during the Fifth Plan. According to the relaxed conditions, colleges in backward and rural areas offering three-year degree courses will be eligible for development grants if they have 300 students and 15 teachers against the normal requirement of 400 and 20 respectively. In the case of colleges offering two-year degree courses, the normal requirement of 270 students and 15 teachers is relaxed to 200 and 10 respectively.

(b) and (c). The criteria for providing general development assistance to colleges during the Sixth Plan have not so far been finalised by the Commission.

Opening of new branch Post Offices during Sixth Five Year Plan

3279. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how many rural branch post offices are proposed to be opened in the 6th Five Year Plan and its State-wise break-up, if any;

(b) the proposed expenditure to be incurred by the Union Government on this score; and

(c) the number of branch post offices to be upgraded to the rank of Sub-Post offices alongwith State-wise break-up if any?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): (a) and (b). The Five Year Plan for the period 1980—85 is under preparation. The number of rural post offices to be opened during this Plan period in the country and the expenditure to be incurred on this score will be known when the Plan is finalised with the approval of the Planning Commission. Circle-wise targets are assigned on a year to year basis and not for the 5 year period as a whole.

(c) Upgradation of extra departmental branch post offices to the level of sub post office is not a Plan Programme and, therefore, no targets are fixed. Such cases are decided from time to time on the basis of workload, financial results and other relevant considerations.

प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी, दिल्ली

3280. श्री विलोक चन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत सोसाइटी है ;